TO JOIN OUR UPSC PAID GROUP

WHATSAPP GROUP ➡ 9818323004

THE HINDU ANALYSIS – 09 JUNE 2023

संपादकीय 1: हम कम कार्बन वाले शहर में कैसे परिवर्तित हो सकते हैं?

प्रसंग

- 2020 में, शहरों ने 29 ट्रिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ दिया। इसलिए, पर्यावरण पर शहरों के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए, कम कार्बन वाले शहर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कम कार्बन शहर

- एक निम्न-कार्बन शहर या डीकार्बोनाइज्ड शहर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित एक शहर है जो ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के निम्न स्तर का उत्पादन करता है।
- मानव गतिविधि के कारण जीएचजी उत्सर्जन 20वीं सदी के मध्य से देखे गए जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है।
- निम्न-कार्बन या शुद्ध-शून्य शहरों में संक्रमण के लिए हमें कई क्षेत्रों में शमन और अनुकूलन विकल्पों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। इसे '**सेक्टर-कपलिंग एप्रोच**' कहा जाता है, और शहरी प्रणालियों को डीकार्बोनाइज़ करना आवश्यक है।

ऊर्जा-प्रणाली संक्रमण

- एक ऊर्जा-प्रणाली संक्रमण शहरी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को लगभग 74% कम कर सकता है।
- स्वच्छ ऊर्जा और संबंधित प्रौद्योगिकियों में तेजी से प्रगति और कीमतों में गिरावट के साथ, हमने कम कार्बन समाधानों को लागू करने के लिए आर्थिक और तकनीकी बाधाओं को भी पार कर लिया है।
- संक्रमण को मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर लागू किया जाना चाहिए।
- आपूर्ति पक्ष में शमन विकल्पों में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना और कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना शामिल है।

UPSC DESIRE WHATSAPP GROUP 8054138168

- मांग पक्ष पर, 'अवॉइड, शिफ्ट, इम्प्रूव' फ्रेमवर्क का उपयोग करने से सामग्री और ऊर्जा की मांग को कम करना होगा, और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ जीवाश्म ईंधन की मांग को प्रतिस्थापित करना होगा।

- दूसरा, ऊर्जा क्षेत्र में अवशिष्ट उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए, हमें कार्बन-डाइऑक्साइड हटाने (सीडीआर) प्रौद्योगिकियों को लागू करना चाहिए।

- वास्तव में, हमारे पास ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से नेट-जीरो शहरी प्रणाली का निर्माण करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां और ज्ञान का आधार है।

रणनीतियाँ- कोई एक आकार फ़िट दृष्टिकोण नहीं:

- कम कार्बन को कम करने और अनुकूल बनाने की रणनीतियाँ **शहर की विशेषताओं** के आधार पर भिन्न होती हैं।

- यह एक महत्वपूर्ण विचार है जब हम सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से उचित ऊर्जा-संक्रमण नीतियां बनाते हैं। ये विचार एक शहर का स्थानिक रूप, भूमि-उपयोग पैटर्न, विकास का स्तर और शहरीकरण की स्थिति हैं।

- एक स्थापित शहर ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को फिर से तैयार और पुनर्व्यवस्थित कर सकता है, और सार्वजनिक और साथ ही साइकिल चलाने और पैदल चलने जैसे सक्रिय परिवहन को बढ़ावा दे सकता है।

- वास्तव में, लोगों के आस-पास डिज़ाइन किए गए चलने योग्य शहर ऊर्जा की मांग को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन को विद्युतीकृत कर सकते हैं और नवीकरणीय-आधारित जिला कूलिंग और हीटिंग नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं।

- एक तेजी से बढ़ता शहर आवास और नौकरियों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर सकता है - शहर की योजना इस तरह से बनायी जा सकती है कि काम के स्थान आवासीय परिसरों के करीब आ जाएं, इस प्रकार परिवहन ऊर्जा की मांग कम हो जाती है।

- नए और उभरते शहरों में उत्सर्जन को कम करने की सबसे अधिक क्षमता है - ऊर्जा-कुशल सेवाओं और बुनियादी ढांचे का उपयोग करके, और एक जन-केंद्रित शहरी डिजाइन।

UPSC DESIRE WHATSAPP GROUP 8954038168

- वे बिल्डिंग कोड भी लागू कर सकते हैं जो शुद्ध-शून्य ऊर्जा उपयोग को अनिवार्य करते हैं और मौजूदा इमारतों को फिर से तैयार करते हैं, जबकि धीरे-धीरे कम उत्सर्जन वाली निर्माण सामग्री में स्थानांतरित हो जाते हैं।

बस ऊर्जा संक्रमण:

- ऊर्जा प्रणालियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका, स्थानीय आर्थिक विकास और विविध क्षेत्रों में लगे लोगों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण से जुड़ी हैं।

- इसलिए एक आकार-फिट-सभी दृष्टिकोण से सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से न्यायोचित संक्रमण सुनिश्चित करने की संभावना नहीं है।

- मोटे तौर पर, ऊर्जा आपूर्ति को तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग (जैसे शहरीकरण के कारण), ऊर्जा सुरक्षा की जरूरतों और निर्यात के खिलाफ संतुलित करने की आवश्यकता है।

- अतिरिक्त न्याय संबंधी चिंताओं में बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित भूमि बेदखली, गरीबी का स्थानिक संकेंद्रण, कुछ समुदायों का हाशिए पर होना, लैंगिक प्रभाव और आजीविका के लिए कोयले पर निर्भरता शामिल हैं।

निष्कर्ष :

- कम कार्बन वाले शहरों में संक्रमण अनिवार्य रूप से सामाजिक इक्विटी और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता है। यही कारण है कि हमें विभिन्न क्षेत्रों और संदर्भों में जटिल, बहुआयामी मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए, और एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो कई आवाजों और अनुभवों पर ध्यान दे।

UPSC.DESIRE WHATSAPP GROUP 8054098168

संपादकीय 2: कैसे KFON का लक्ष्य केरल में डिजिटल विभाजन को पाटना है

परिचय

- 2019 को, केरल में सरकार ने घोषणा की कि राज्य में इंटरनेट तक पहुंच एक बुनियादी अधिकार होगा, ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेट एक्सेस को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने वाले एक प्रस्ताव को पारित करने के तीन साल बाद आई है। **घोषणा के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत योजना भी थी कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (KFON)** की स्थापना के साथ यह जमीनी हकीकत बन जाएगा।

केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (KFON) के बारे में:

- केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क (KFON) एक क्रांतिकारी सार्वजनिक-वित्त पोषित परियोजना है, जिसकी कल्पना पूरे राज्य में हाई-स्पीड इंटरनेट एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
- KFON को केंद्र सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) दोनों लाइसेंस मिले हैं।
- महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप परियोजना फरवरी, 2021 में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य राज्य में 20 लाख गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना और सार्वभौमिक इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना और डिजिटल विभाजन की समस्या का समाधान करना है।
- KFON Ltd मुख्य रूप से राज्य में संचालित अन्य ISP के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदाता है।

केएफओएन के प्रमुख उद्देश्य:

- सभी सेवा प्रदाताओं के लिए गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच के साथ एक कोर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर (सूचना राजमार्ग) बनाएं ताकि वे अपने कनेक्टिविटी गैप को बढ़ा सकें।
- सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि को जोड़ने वाला एक विश्वसनीय, सुरक्षित और स्केलेबल इंट्रानेट प्रदान करें।
- आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए एमएसओ, टीएसपी, आईएसपी के साथ साझेदारी।

UPSC DESIRE WHATSAPP GROUP 854038168

केएफओएन के लाभ

- KFON राज्य में मौजूदा दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र का पूरक होगा और केरल को एक गिगाबिट अर्थव्यवस्था के रूप में सही उत्प्रेरक स्थिति के रूप में कार्य करेगा। बोर्ड भर में महसूस किए जाने वाले कई लाभों में से कुछ निम्नलिखित हैं।
- इंटरनेट एक्सेस को नागरिकों का मूल अधिकार बनाकर डिजिटल डिवाइड को पाटना और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को मुफ्त इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को सक्षम बनाना।
- इस नेटवर्क का लाभ उठाकर टीएसपी/आईएसपी/केबल ऑपरेटरों के माध्यम से नागरिकों को ई-गवर्नेंस प्रदान करें।
- इस नेटवर्क का लाभ उठाकर प्रतिस्पर्धी बाजार के कारण टीएसपी/आईएसपी/केबल ऑपरेटरों द्वारा घरों में सस्ती और बेहतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करें।
- स्थानीय उद्यमों और एसएमई के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा समर्थन प्रदान करके और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- मानव पूंजी विकास
- दूरस्थ शिक्षा प्रदान करें
- रोजगार के अवसर सृजित करें
- कौशल बढ़ाएँ
- दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें
- बुनियादी ढांचे का विकास
- स्मार्ट सिटी/स्मार्ट ग्रिड
- परिवहन प्रबंधन
- कम्युनिटी कनेक्ट - स्मार्ट विलेज
- इंफोटेनमेंट
- सूचना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना (वित्तीय सेवाएं, ई-गवर्नेंस, कृषि तकनीक)
- मनोरंजन (आईपीटीवी, ओटीटी, आदि)

UPSC DESIRE WHATSAPP GROUP 8054038168

- नवाचार
- जुड़े हुए समुदाय बनाना (शोधकर्ता, उत्पाद विकास, कभी भी कहीं भी/कभी भी सहयोग)

राष्ट्रीय स्तर पर के-फॉन परियोजना की आवश्यकता:

- **सामाजिक न्याय:** डिजिटल असमानताएँ घोर सामाजिक अन्याय की ओर ले जाती हैं और व्यक्तियों के विकास में बाधा डालती हैं। इस प्रकार, ऐसी असमानताओं को कम करने के लिए इंटरनेट प्रदान किया जाना चाहिए।
- **सेवाओं तक पहुंच:** हाल के दिनों में, कई सरकारी और निजी क्षेत्र की सेवाएं डिजिटल हो गई हैं। इस प्रकार, गरीब से गरीब व्यक्ति को इंटरनेट प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था:** हम एक वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां डिजिटल प्रक्रियाओं का ज्ञान लोगों के काम करने, सहयोग करने, सूचनाओं का उपभोग करने और खुद का मनोरंजन करने के तरीके को बदल देगा। इसे सतत विकास लक्ष्यों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया है और इसने डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाया है।
- **बहिष्करण को रोकना** : सेवाएँ अब कम लागत और बेहतर दक्षता के साथ ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं। यह नागरिकों को निचले स्तर की सरकारी नौकरशाही को बायपास करने की भी अनुमति देता है।
- **सुशासन** : इंटरनेट पहुंच और डिजिटल साक्षरता में आवश्यक प्रगति के बिना शासन और सेवा वितरण को ऑनलाइन करना आर्थिक अर्थ नहीं रखता है।
- **रोजगार के अवसर:** इंटरनेट पहुंच की कमी कई लोगों को समान रोजगार के अवसरों से रोकती है, जो इंटरनेट का उपयोग और डिजिटल ज्ञान रखने वालों के लिए उपलब्ध है।
- **महिला सशक्तिकरण:** डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट का उपयोग महिला अधिकारों को आगे बढ़ाने में मदद करता है और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने में मदद करता है।

निष्कर्ष

- सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्थानीय निकायों के माध्यम से जमीनी स्तर पर एक डिजिटल साक्षरता अभियान भी शुरू किया है कि हर कोई इंटरनेट के माध्यम से बुनियादी सेवाओं का उपयोग करने के लिए सुसज्जित है। यदि KFON

UPSC.DESIRE WHATSAPP GROUP 8051038168

परियोजना ने वह हासिल किया है जिसकी उसने परिकल्पना की है, तो जहां तक पहुंच और अवसरों का संबंध है, यह जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकता है।

Click here upsc.desire

Click here everyday.current.gk

UPSC.DESIRE WHATSAPP GRO